पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ''गाली'' निकाली

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर आपत्ति जताई तो सभापति ने अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। पूर्व यूडीएच मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ''गाली'' निकाल दी। जिस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई, इसके बाद सभापति ने उनके द्वारा बोले गए अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकलवाया।

दरअसल धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कहा था कि ''अगर लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य नहीं बनाया तो यह युवा आबादी चुनौती बन जाएगी।'' उनके इस बयान के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा '' इस देश में एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया।'' इस दौरान गर्ग को जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा, आपकी बात आधी समझ आती है....लेकिन आधी नहीं। इसी दौरान धारीवाल ने गर्ग को संबोधित करते हुए गाली निकाल दी।

धारीवाल की बात खत्म करने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक ने खड़े होकर आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा कि आदत के मुताबिक धारीवाल ने आज सदन में फिर गाली दी है, उसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। जिस पर सभापति ने गाली को कार्यवाही से हटाने के आदेश दिए। ज्ञात रहे कि शांति धारीवाल पहले भी सदन मं गाली दे चुके हैं, उस वक्त भारी हंगामा हुआ था और उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ी थी।

- इससे पूर्व धारीवाल ने प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
- उन्होंने सड़कों के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी द्वारा सदन में दिए गए जवाब में भी झूठ बोलने के आरोप लगाए

इससे पहले शांति धारीवाल ने जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं सड़कों के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी पर भी सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए।

धारीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना को लेकर सीएजी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है।

रिपोर्ट में एक करोड़ 32 लाख में से 95 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी पाए गए है। धारीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से फर्जी स्किल सेंटर खुलवा दिए हैं, इसलिए घोटाला किया गया है। बैंक खातों का कोई विवरण नहीं है, फर्जी फोटो और फर्जी फिंगरप्रिंट और एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान किया गया है। धारीवाल ने कहा कि जिन युवाओं ने आपको सत्ता में बैठाया है, कल वही आपके लिए चुनौती बन सकते है।

हमारे कार्यकाल में 70 हजार किमी सड़कें बनीं

शांति धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी है, जबकि पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2024-25 में आई थी, उसमें पेज नंबर 12 पर लिखा है कि कांग्रेस के शासन में 70 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई है। धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सदन में झूठ बोला है।

धारीवाल ने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में 14,800 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है, जबकि हमारी सरकार के दो साल के शासन में ही 23 हजार 585 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यह भी पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से झूठे भाषण सदन में नहीं देना चाहिए था।

नाम हटाने से विचारधारा खत्म नहीं होगी

धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक-एक करके हमारी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे है। हमने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वो गरीबों, छात्रों और मजदूर किसानों के हित की योजनाएं थी। मनरेगा में ग्राम सभा का अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया है।

शांति धारीवाल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अहिंसा के आविष्कार करने वाले महात्मा गांधी का नाम ही योजनाओं से हटाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि ''महात्मा गांधी का नाम दुनिया की जबान, दुनिया के दिल और दुनिया के दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। महात्मा गांधी की मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते है।''

ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक 77 लाख प्रकरण निस्तारित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास धरातल पर हो रहे साकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। अब 5 से 9 फरवरी तक ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा।

गत 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इन शिविरों क शुरुआत की गई थी और इनसे किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

इन शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में एक हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरूष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में

- 5 से 9 फरवरी तक ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण होगा

मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौंड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयत्र, प्लास्टिक मल्च के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य कराए जा रहे हैं।

''खेजड़ी बचाओ'' आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

कांग्रेस विधायक डूंगरराम ने कहा कि ''लाखों लोग महापड़ाव में बैठे है, 29 संत और 339 पुरूष आमरण अनशन पर हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की।''

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल में पर्ची के जरिए मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति बिश्नोई समाज की अगुवाई में पिछले दो साल से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, इसे बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। गेदर ने कहा कि सरकार को पता था इसके बावजूद आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की।

लाखों लोग महापड़ाव में आए। आज तीसरे दिन भी 29 संत अन्न, जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। करीब 339 पुरुष अन्न,जल त्याग कर बीकानेर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तीन धरनार्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है, कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि ''साधु संत धरने पर बैठे हैं, सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें''

पर नहीं गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें। खेजड़ी राज्य वृक्ष नहीं देव वृक्ष भी है, लोग पूजते हैं। आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी है। कांग्रेस विधायक डूंगरराम गेदर ने कहा कि 10 नवंबर 2024 को जब बिश्नोई समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव डाला था। उस समय खींवसर का उपचुनाव था। सरकार को लगा कि खींवसर का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन दिया गया। चुनाव निकल गया, चुनाव जीत लिया, मुद्दे को जुमले की टोकरी में डाल दिया गया, कानून क्या बनाना था।विधायक डूंगरराम ने कहा कि, एक साल बाद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेड़ काटने पर 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग की लकड़ी काटने पर जो 6 महीने की सजा थी, उसकी जगह मात्र 5000 रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की और आसानी से परमिशन मिल गई। आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं?

डॉ. लीलाधर दोचानिया के कविता संग्रह का विमोचन कल

जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत उप निदेशक डॉ. लीलाधर दोचानिया के नव प्रकाशित कविता संग्रह ''जिन्दगी मुस्कुराते रहे'' का विमोचन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक त्रिलोक चंद कौशिक करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित साहित्य संगीत और चित्रकला के त्रिआयामी उत्सव पिंकफेस्ट के दौरान महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार मनीषा खटाते सहित विभिन्न स्थानों के अनेक लेखक भाग लेंगे। संयोजन सीमा वालिया करेंगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति भारी उत्साह

जयपुर (कासं)। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। करीब 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी

- 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक लोगों ने किया आवेदन
- योजना में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
- 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी का प्रावधान

को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के प्रति युवाओं की बेहतर प्रतिक्रिया रही है। अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है, 22 जनवरी को आवेदन शुरू किए गए थे। जिला महाप्रबंधकों द्वारा इन आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए शीघ्र ही बैंकों को अग्रेषित किए जाएंगे।

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन

जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही, चूरू, बीकानेर, टोंक, और हनुमानगढ़ जिलों में 200 से अधिक आवेदन आए हैं। बूंदी, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, दौसा, डीडवाना कुचामन, बारां, झुंझुनूं, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, पाली और अलवर जिले ऐसे हैं, जहां 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।ज्ञात रहे कि इस योजना में 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षिणक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

'धौराला में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन कार्य अग्रिम चरण में है'

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के धौराला राजस्व गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आंवटन का काम अग्रिम चरण में है।

कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) में आने के कारण इसका उपयोग उद्योगों के लिए नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल 114 प्लॉट उपलब्ध हैं, इनमें 110 प्लॉट आवंटित तथा 4 रिक्त हैं। इस क्षेत्र में कुल 40 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 25 एकड़ उद्योगों तथा शेष भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग स्थापित हैं। खनन प्रतिबंधों के कारण इन उद्योगों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों को देखते हुए राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए राजस्व गांव धौराला में 27.68 हैक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड के ग्राम मुण्डजोडी में 27.37 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिह्नित भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर व राजस्व विभाग को समय-समय पर लिखा गया है।

- उद्योग मंत्री ने कर्नल राठौड़ सदन में बताया कि ''राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके।''

'आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा पोषाहार दे रहे, जिन्हें कुत्तें भी नहीं खाए'

जयपुर (विसं)। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया ने जनजाति मंत्री पर आरोप लगाते हुए तंज कसे। मां बाड़ी केंद्रों पर 4-4 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा।

जो पोषाहार आ रहा है, जो एक रुपए के बिस्किट का पैकेट आ रहा है, उसको कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा पोषाहार पहुंच रहा है, जो कुत्ते भी नहीं खाए, आप चेक करो। आप मंत्री हो, चेक क्यों नहीं करते हैं। इस पर टीएडी मंत्री ने कहा कि आपकी अध्यक्षता में ही कमेटी बना देता हूं। इससे पहले उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी के लोग लगने चाहिए, लेकिन आपने जनरल को लगा दिया। मंत्री ने अपने रिश्तेदारों के कहने पर टीएसपी क्षेत्र में नौकरी लगा दी। गत 3-4 महीने से शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, चेक करके देखो।

भजनलाल सरकार ने मजबूत की प्रदेश में महिला सुरक्षा : बेढ़म

जयपुर। राजस्थान 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रदेश में महिला अपराधों की स्थिति, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी। मंत्री बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधों में कमी देखने को मिली है।

गृह राज्य मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में महिला अत्याचार के 41 हजार 155 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 42 हजार 174 रही।

इसके बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रभावी पुलिस कार्रवाई और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के कारण वर्ष 2024 में प्रकरण घटकर 37 हजार 700 रह गए तथा वर्ष 2025 में 37 हजार 981 प्रकरण दर्ज हुए।

उन्होंने कहा कि यह कमी पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, त्वरित अनुसंधान और सरकार की प्राथमिकताओं का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारियों को 60 दिवस की निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश हैं।

थाईलैंड की राजकुमारी 6 से 10 फरवरी तक रहेंगी राजस्थान प्रवास पर

मुख्य सचिव ने की रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट के साथ तैयारियों की समीक्षा

जयपुर (कासं)। थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उनकी यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पूरे विश्व में अतिथि देवो भव: की परंपरा की अपनी अनूठी पहचान है। ऐसे में प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या की मेहमान नवाजी का अवसर मिलना राज्य के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि थाई राजकुमारी का यह दौरा भारत-थाईलैंड संबंधों में और अधिक गहरे सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा।

मुख्य सचिव ने प्रिंसेस की यात्रा के दौरान पुलिस तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों, यातायात व्यवस्था, प्रोटोकॉल, संबंधी समस्त पहलूओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना राजकन्या अपने प्रवास के दौरान जयपुर एवं जोधपुर का भ्रमण करेंगी। जयपुर में वे आमेर किला, हवामहल, सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार सहित अन्य प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेंगी। इसके पश्चात जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है। इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प कला, शिल्पकला, संस्कृति,

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने थाईलैंड की राजकुमार के राजस्थान यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की।

विरासत एवं पारंपरिक आतिथ्य से भी अवगत कराया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, महानिदेशक पुलिस, (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, आयुक्त पर्यटन विभाग रूक्मणि रियार, जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के साथ थाई एम्बेसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इनके साथ ही पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह, जोधपुर कलेक्टर गौरव गोयल, जोधपुर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

आवासहीन परिवारों की संख्या के सवाल पर मंत्री खर्रा और सुभाष गर्ग के बीच नोंकझोंक

दरअसल प्रश्नकाल में आर.एल.डी. विधायक सुभाष गर्ग ने आवासहीन परिवारों की संख्या पूछी थी, लेकिन यू.डी.एच. मंत्री खर्रा पीएम आवास योजना को लेकर जवाब देने लगे थे

जयपुर (विसं)। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी सदन में विपक्ष के सवालों में उलझकर रह गए। प्रश्नकाल के दौरान विवाद की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के सवाल से हुई। गर्ग ने भरतपुर में आवासहीन परिवारों की संख्या और पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों पर सवाल पूछा था। सही जवाब नहीं मिलने पर विधायक सुभाष गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बहस और नोंकझोंक होत रही।

मंत्री खर्रा के जवाब से असंतुष्ट सुभाष गर्ग ने कहा कि पहले आवासहीन परिवारों की संख्या बताइए। जिस पर मंत्री खर्रा, पीएम आवास योजना की पात्रता की शर्तें बताने लगे। उनके जवाब पर गर्ग ने आपत्ति करते हुए कहा कि होमलेस पॉलिसी-2022 में आवासहीन परिवारों के सर्वे करने का प्रावधान है या नहीं। मैंने तो इस पर जवाब मांगा था। मैं तो हां-ना में जवाब मांग रहा हूं।

- इस बीच अन्य मंत्रियों ने मंत्री के पक्ष में जवाब देने की कोशिश की तो नेता प्रतिपक्ष ने भी आपत्ति जताई

जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भरतपुर में पीएम आवास योजना के 80 फीसदी पूरे हो चुके है। गर्ग ने कहा कि, भूमिहीन परिवारों की संख्या पर सवाल किया है। जिनके पास भूमि ही नहीं है वो आावासहीन कैसे होगा? आवासहीन तो उस दिन होगा जिस दिन भूमि होगी। जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो बेघर कहलाएगा। आवासहीन नहीं। जिसके पास रहने का ठौर नहीं, वो बेघर है। जिसके पास मकान नहीं है, लेकिन जमीन है वो आवासहीन कहलाएगा।

इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर तक नोंकझोंक होती रही। यूडीएच मंत्री ने कहा कि भूमिहीन परिवारों की संख्या चाही है तो कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर दे देंगे।

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यूडीएच मंत्री के जवाब के बीच दो मंत्रियों के खड़े होने पर तंज कसते हुए कहा कि यहां एडवोकेट की जरूरत नहीं होती।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि आप साल पूछिए भाषण देने का अधिकार नहीं है। जूली ने कहा सच्चाई बता दी तो कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जूली ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री जल्दीबाजी कर गए। उन्होंने आवासहीन का सवाल पूछा था, सदस्य ने गलती कर दी कि होमलेस पॉलिसी पर पूछ लिया। इन्होंने आवासहीन समझ लिया बात एक ही है। सवाल इतना सा है कि जिनके पास मकान नहीं है मकान कब तक दोगे?

जवाब गलत आया इसलिए कहा कि 2022 में जब होमलेस पॉलिसी आ गई, तो उसका मापदंड पूछे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने खुद को ज्यादा काबिल साबित करने के चक्कर में मंत्रीजी को और मरवा दिया।